- 19th Year
- Issue: 199
- 21.11.2025 (FRIDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

आदिवासी समुदायों का विकास प्राथमिकता, उग्रवाद पर लगाम–राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा ऐलान

अंबिकापुर २०/११ (संवाददाता): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को छज़ीसगढ़ सरकार द्वारा अंबिकापुर में बिरसा मुंडा सहित आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सज़्मानित करने के लिए आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुईं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समुदायों का योगदान भारत के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय है। आदिवासियों का विकास भारत सरकार की प्राथमिकता है। आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की योजनाएँ विकसित और कार्यान्वित की गई हैं। राष्ट्रपति ने राज्य की प्रगति के लिए लोगों को बधाई दी। इस अवसर पर छज़ीसगढ़

के राज्यपाल रमेन डेका और मुज़्यमंत्री विष्णु देव साय भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैं छज़ीसगढ़ के लोगों को उनकी प्रगति के लिए बधाई देती हूँ। उन्होंने अभी-अभी राज्य गठन की रजत जयंती मनाई है। मुझे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली (झारखंड में) जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय इतिहास में आदिवासी समुदायों का योगदान अतुलनीय रहा है। छज़ीसगढ़ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड और ओडिशा छज़ीसगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे राज्य ने अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा है, जो सार्वजनिक स्थानों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।मुर्मू ने कहा कि जब मैं हेलीपैड से यहाँ आ रही थी, तो रास्ते में छज़ीसगढ़ की संस्कृति साफ़ दिखाई दे रही थी। राज्य ने अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा है जो बहुत प्रभावशाली और मनभावन है... मुझे आदिवासी होने पर बहुत गर्व है। आदिवासी कला और संस्कृति को देश के साथ-साथ विदेशों में भी और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद का रास्ता छोड़कर मुज़्यधारा में शामिल होने के लिए लोगों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, छज़ीसगढ़ सहित देश भर के लोग वामपंथी उग्रवाद का रास्ता छोड़कर विकास की मुज़्यधारा में शामिल हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के सुविचारित और सुव्यवस्थित प्रयासों से निकट भविष्य में वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन संभव हो जाएगा। इससे पहले, राज्यपाल रमेन डेका और मुज़्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा जिले के अंबिकापुर पहुँचने पर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी छज़ीसगढ़ दौरे का स्वागत करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है।

दिल्ली विस्फोट में चार और आरोपी गिरफ़्तार, जमू-कश्मीर से हिरासत में लिया

नयी दिल्ली २०/११ (संवाददाता):राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए विस्फोट के चार और मुज़्य आरोपियों को गिरज़्तार किया है, जिससे गिरज़्तारियों की कुल संज़्या छह हो गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी पेशी आदेश पर चारों आरोपियों को जज़्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हिरासत में लिया गया। इनकी पहचान जज़्मू-कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉ. मुज़्ज़िमल शकील गनई, जज़्मू-कश्मीर के अनंतनाग निवासी डॉ. अदील अहमद राथर, उज़र प्रदेश के लखनऊ निवासी डॉ. शाहीन सईद और जज़्मू-कश्मीर के शोपियां निवासी मुज़्ती इरफान अहमद वागे के रूप में हुई है। एजेंसी के अनुसार, इन सभी ने इस हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।इससे पहले, एजेंसी ने दो अन्य आरोपियों, आमिर राशिद अली, जिसके नाम पर विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार पंजीकृत थी, और जसीर बिलाल वानी उर्फ ??दानिश, जिसने हमले में शामिल आतंकवादी को तकनीकी सहायता प्रदान की थी, को गिरज़्तार किया था। मामले की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के प्रयासों के तहत उनसे पूछताछ जारी है। घटना के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाँच एजेंसी को सौंप दी थी। एजेंसी विभिन्न राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर हमले के लिए ज़िज़्मेदार समूह के प्रत्येक सदस्य का पता लगाने और उसे गिरज़्तार करने के लिए काम कर रही है।

बिहार में एनडीए की सरकार, पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को सराहा, बताया कुशल और अनुभवी प्रशासक

पटना २०/११ (संवाददाता): जनता दल-यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक भव्य समारोह में रिकॉर्ड दसवीं बार बिहार के मुज़्यमंत्री पद की शपथ ली। कुल 18 कैबिनेट मंत्रियों और दो उप-मुज़्यमंत्रियों ने शपथ ली। कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और एनडीए के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए। इस समारोह में एनडीए शासित कई राज्यों के मुज़्यमंत्रियों ने भी भाग लिया। शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और अन्य मंत्रियों को बधाई दी है। शपथ की तस्वीरों को साझा करते

हुए पीएम मोदी ने कहा कि श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुज़्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत-बहुत बधाई। वे एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं। राज्य में सुशासन का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।

नए कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं! उन्होंने आगे लिखा कि श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी को बिहार के उप मुज़्यमंत्री बनने पर ढेरों बधाई।

जमीनी स्तर पर दोनों नेताओं के पास जनसेवा का लंबा अनुभव है। उन्हें भी मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं! मोदी ने एज़्स पर यह भी लिखा कि बिहार सरकार में मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को मेरी हार्दिक बधाई। समर्पित नेताओं की यह एक ऐसी शानदार टीम है, जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

नीतीश कुमार ने बिहार के 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली

पटना २०/११ (संवाददाता): बिहार के मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार पद की शपथ ली, जो राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पटना के गांधी मैदान में आयोजित उत्सवी समारोह में नीतीश कुमार के साथ 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल आरिफ मोहमद खान ने सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मंत्रिमंडल में भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उपमुज़्यमंत्री बनाया गया है।शपथग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी ने एज़्स पर लिखा-नीतीश कुमार जी को बिहार के मुज़्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत-बहुत

बधाई। वे एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं। राज्य में सुशासन का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नए कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं! मंत्रिमंडल में विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, जिसमें भाजपा को 14, जनता दल (यूनाइटेड) को 8, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 स्थान मिला है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए युवा और अनुभवी नेताओं का चयन किया गया, जिसमें एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। नए मंत्रियों में श्रेयसी सिंह, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रौशन, संजय कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश जैसे नाम प्रमुख हैं। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 16 राज्यों के मुज़्यमंत्री समेत विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का अभिवादन किया और गमछा लहराकर उत्साह बढ़ाया, जिसका जनसमूह ने भी जोरदार स्वागत किया। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। वे किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें विधान परिषद में मनोनीत किया जाएगा। पहले उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा का नाम चर्चा में था, जो पहली बार विधायक चुनी गई हैं। जीतन राम मांझी के पुत्र और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को दोबारा मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में उनके पास लघु जल संसाधन मंत्रालय था। हम से इस बार पांच विधायक चुनकर आए हैं। सबसे कम उम्र की मंत्री श्रेयसी सिंह (34) बनी हैं, वहीं बिजेंद्र प्रसाद यादव (79) सबसे बुजुर्ग मंत्री बने हैं। श्रेयसी पूर्व रेल राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं। कॉमनवेल्थ गेम में शूटिंग में गोल्ड ले चुकी हैं। बिजेंद्र प्रसाद यादव 9वीं बार जीतकर विधासभा पहुंचे हैं।

नीतीश के रिकॉर्ड पर तेजस्वी की बधाई, नई सरकार से बताई ये बड़ी उमीद

पटना २०/११ (संवाददाता): नीतीश कुमार के लगातार पांचवीं बार बिहार के मुज़्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने सज़ारूढ़ एनडीए गठबंधन को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उज़्मीद है कि नई सरकार लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। बिहार के मुज़्यमंत्री और उनके मंत्रियों के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद तेजस्वी ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार को बिहार के मुज़्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएँ जिन्होंने मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली है।

राजद नेता ने कहा कि मुझे उज़्मीद है कि नई सरकार ज़िज़्मेदार नागरिकों की आकांक्षाओं और उज़्मीदों पर खरी उतरेगी, अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी और बिहार के लोगों के जीवन में सकारात्मक और गुणात्मक

बदलाव लाएगी। नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक पाँचवीं बार मुज़्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह वे राज्य के सबसे लंबे समय तक मुज़्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं और उन्होंने रिकॉर्ड दसवीं बार शपथ भी ली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के अन्य प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में भाजपा नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी बिहार के उपमुज़्यमंत्री पद की शपथ ली। दोनों उपमुज़्यमंत्रियों के अलावा 18 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी की पार्टी ने शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चुनाव में उतार-चढ़ाव आना तय है और पार्टी गरीबों की आवाज़ उठाती रहेगी। राजद ने एज़्स पर एक पोस्ट में कहा कि जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है। इसमें उतार-चढ़ाव आना तय है। हार में कोई गम नहीं, जीत में कोई अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। यह गरीबों के बीच उनकी आवाज़ उठाती रहेगी।

रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दायर किया नया आरोपपत्र

नयी दिल्ली २०/११ (संवाददाता): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ब्रिटेन स्थित रक्षा डीलर संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक नया आरोपपत्र दायर किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति वाड्रा तीन अलग-अलग धन शोधन मामलों में ईडी की नज़र में हैं, जिनमें से दो हरियाणा और राजस्थान में भूमि सौदों में कथित अनियमितताओं से संबंधित हैं। अप्रैल में, 2008 के हरियाणा भूमि सौदे के सिलसिले में उनसे लगातार तीन दिनों तक पूछताछ की गई थी। एक अन्य मामला राजस्थान के बीकानेर में एक भूमि सौदे में कथित विज़ीय अनियमितताओं से संबंधित है।यह मामला 2023 के आरोपपत्र में दर्ज ईडी के निष्कर्षों से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संजय भंडारी ने 2009 में लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर में एक

संपज़ि अर्जित की और इसका वाड्रा के निर्देशों के अनुसार नवीनीकरण कराया और नवीनीकरण के लिए धन रॉबर्ट वाड्रा द्वारा प्रदान किया गया। आरोपपत्र में दावा किया गया है कि वाड्रा ने नवीनीकरण के लिए धन मुहैया कराया था। हालाँकि, वाड्रा ने लंदन में किसी भी संपज़ि के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व से लगातार इनकार किया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें परेशान और परेशान किया जा रहा है।

नीतीश कुमार के सीएम पद पर वापसी पर अखिलेश की बधाई, समाजवादी मूल्यों वाले शासन की जताई उमीद

लखनऊ २०/११ (संवाददाता): उज़र प्रदेश के पूर्व मुज़्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुज़्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी और पूरे पाँच साल के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएँ दीं। अपने संदेश में, अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का मुज़्यमंत्री पद पर लौटना बिहार के राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार विकास और सामाजिक न्याय पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य का नेतृत्व करेंगे।अखिलेश यादव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नीतीश कुमार ने समाजवादी मूल्यों पर आधारित शासन की लगातार वकालत की है और आशा व्यक्त की कि उनका नया कार्यकाल समावेशिता, कल्याणकारी

नीतियों और जनहितैषी निर्णय लेने के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करेगा। उन्होंने कहा कि मैं श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुज़्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं उनकी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित एक स्वतंत्र शासन मॉडल को अगले पाँच वर्षों तक सफलतापूर्वक चलाने और लोगों के लिए सकारात्मक और कल्याणकारी पहल सुनिश्चित करने की भी कामना करता हूँ।

समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि बिहार और उज़र प्रदेश गहरे सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध साझा करते हैं और आशा व्यक्त की कि दोनों पड़ोसी राज्य क्षेत्रीय विकास के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने आज दिन में अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ शपथ ली। अखिलेश यादव का संदेश देश भर के नेताओं की बधाई प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला में जुड़ गया है, जिससे बिहार में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हुई है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए एक अग्निपरीक्षा माने जा रहे थे, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में हर चुनाव में बिहार की राजनीति को अपने इर्द-गिर्द घुमाया है।

विविध समाचार

चुनाव आयोग पर बरसीं ममता, एसआईआर प्रक्रिया को बताया खतरनाक

कोलकाता २०/११ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य में मतदाता सूचियों के संरचनात्मक रूप से अस्वस्थ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अज़्यास पर अपनी चिंता व्यक्त की। 20 नवंबर को मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे एक पत्र में मुज़्यमंत्री बनर्जी ने दावा किया कि प्रशिक्षण में गंभीर कमियाँ, अनिवार्य दस्ता वेज़ीकरण पर स्पष्टता का अभाव और अपनी आजीविका के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच मतदाताओं से मिलना लगभग असंभव होने के कारण यह अज़्यास संरचनात्मक रूप से अस्वस्थ हो गया है। मुज़्यमंत्री ने चल रहे एसआईआर के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें अपर्याप्त योजना, प्रशिक्षण की कमी और अवास्तविक समयसीमा का हवाला दिया गया, जो प्रक्रिया की विश्वसनीयता से समझौता कर रहे हैं। पत्र में लिखा है कि मैंने बार-बार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और जिस तरह से इसे लोगों पर थोपा जा रहा है, उसके संबंध में अपनी गंभीर चिंताओं को उठाया है। अब, मैं आपको यह लिखने के लिए बाध्य हूँ ज़्योंकि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी स्थिति बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुँच गई है। जिस तरह से यह प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वह न केवल अनियोजित और अव्यवस्थित है, बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना या स्पष्ट संचार के अभाव ने पहले दिन से ही इस प्रक्रिया को पंगु बना दिया है। मुज़्यमंत्री बनर्जी ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर अत्यधिक कार्यभार और दबाव को उजागर किया, जो ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि, सर्वर समस्याओं और अपर्याप्त प्रशिक्षण से जूझ रहे हैं, जिससे गलत मतदाता डेटा का खतरा है। पत्र में कहा गया मैं इन अत्यंत विकट परिस्थितियों और भारी कार्यभार के बीच बीएलओ द्वारा किए गए अथक प्रयासों की तहे दिल से सराहना करती हूँ। हालाँकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीएलओ को इस तरह के विशाल कार्य के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण, सहायता और समय नहीं दिया गया है। अवास्तविक कार्यभार, असंभव समय-सीमा और ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि के लिए अपर्याप्त सहायता ने सामूहिक रूप से पूरी प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। यह हमारे चुनावी लोकतंत्र की नींव पर प्रहार है। उन्होंने आगे दावा किया कि बीएलओ अब मानवीय सीमाओं से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं। उनसे अपने मुज़्य कर्तव्यों (जिनमें से कई शिक्षक और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं) को संभालने की उज़्मीद की जाती है, साथ ही साथ घर-घर जाकर सर्वेक्षण और जटिल ई-प्रस्तुतियों को भी संभालना होता है। अधिकांश बीएलओ प्रशिक्षण की कमी, सर्वर की विफलता और बार-बार डेटा बेमेल होने के कारण ऑनलाइन फॉर्म भरने में संघर्ष कर रहे हैं।

नीतीश के मंत्रिमंडल का जातिगत गणित, अगड़ा, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित... किसे मिला कितना प्रतिनिधित्व?

पटना २०/११ (संवाददाता): बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए को भारी जीत दिलाने के कुछ ही दिनों बाद, जेडी(यू) प्रमुख नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुज़्यमंत्री पद की शपथ ली। 74 वर्षीय समाजवादी नेता, जिनकी प्रासंगिकता पर चुनावों से पहले बार-बार सवाल उठाए गए थे, ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ उप-मुज़्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहज़्मद खान ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया। जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुज़्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए के नेतृत्व वाले नए बिहार मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के अलावा कुल 25 नेताओं ने शपथ ली।

मंत्रियों को लेकर जातीय और सामाजिक समिकरणों का ध्यान रखा गया है। फॉर्मूले के तहत, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 17 मंत्री पद आवंटित किए गए हैं (साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का पद जो वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को मिलने की उज़्मीद है), जेडीयू को 15 (मुज़्यमंत्री के रूप में कुमार सहित), जबकि एलजेपी (रामविलास), एचएएम (सेज़्युलर), और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को क्रमश: दो, एक और एक मंत्री पद दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में बीजेपी ने खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखा है।

इनमें सम्राट चौधरी (भाजपा), विजय कुमार सिन्हा (भाजपा), विजय कुमार चौधरी (जद-यू), बिजेंद्र प्रसाद यादव (जद-यू), श्रवण कुमार (जद-यू), मंगल पांडे (भाजपा), दिलीप कुमार जयसवाल (भाजपा) और अशोक चौधरी (जद-यू) शामिल थे। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में लेसी सिंह (जेडी-यू), मदन सहनी (जेडी-यू), नितिन नबीन (बीजेपी), राम कृपाल यादव (बीजेपी), एचएएम (एस) के संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार (जेडी-यू), मोहज़्मद जमा खान (जेडी-यू) और संजय सिंह टाइगर (बीजेपी) शामिल हैं।

इस सूची में अरुण शंकर प्रसाद (बीजेपी), सुरेंद्र मेहता (बीजेपी), नारायण प्रसाद (बीजेपी), रमा निषाद (बीजेपी), लखेंद्र कुमार रौशन (बीजेपी) और श्रेयशी सिंह (बीजेपी) भी शामिल हैं। इसके अलावा, प्रमोद कुमार (बीजेपी), एलजेपी (आरवी) के संजय कुमार, एलजेपी (आरवी) के संजय कुमार सिंह और आरएलएम के दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। 26 मंत्रियों में एक मुस्लिम है तो वहीं, 3 महिलाएं और 3 फर्स्ट टाइमर को मौका दिया गया है। मंत्री बनाए गए नेताओं 8 अगड़ी जाति से हैं। इसमें भाजपा के 5 हैं, तो जेडीयू के और एलजेपी-आर के एक हैं।

इसमें दो भूमिहार, चार राजपूत, एक ब्राह्मण और एक कायस्थ समाज से मंत्री हैं। ओबीसी-ईबीसी समुदाय से एनडीए सरकार में कुल 12 मंत्री से बने हैं। इसमें भाजपा कोटे 8, जेडीयू ने 3 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (ररर) से एक मंत्री बनाए गए हैं। दलित समुदाय से 5 मंत्रियों में बीजेपी कोटे से दो और जेडीयू से एक हैं, तो एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने भी एक-एक मंत्री हैं।

कोयंबटूर में मोदी ने खोला प्राकृतिक खेती का नया द्वार, किसानों को 18000 करोड़ की सौगात

कोयंबटूर २०/११ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और नौ करोड़ किसानों के लिए पीएम-किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपये की 21वीं किस्त जारी करेंगे।

पीएमओ की एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश पहुँचेंगे और पुट्टपर्थी, आंध्र प्रदेश में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर और महासमाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने से देश भर के नौ करोड़ किसानों को लाभ होगा। प्रत्येक पात्र किसान को तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वणक्कममोदी अभियान शुरू किया और उन्हें प्रत्येक किसान का सच्चा मित्र बताया। भाजपा कोयंबटूर दक्षिण की विधायक और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने एज़्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री आज एक व्यस्त कार्यक्रम के लिए कोयंबटूर पहुंचेंगे। दोपहर 1.05 बजे रोड शो की योजना है - जो तमिलनाडु के अटूट समर्थन का एक भव्य प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा, कोयंबटूर प्रेरणा और विकास की एक नई लहर का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री पुट्टपर्थी में दिवंगत आध्यात्मिक नेता श्री सत्य साई बाबा के शताज़्दी समारोह में भाग लेने के बाद आंध्र प्रदेश से दोपहर डेढ़ बजे दक्षिण भारत की कपड़ा राजधानी पहुंचेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि यह आयोजन महत्वपूर्ण है ज़्योंकि पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त देश भर के मेहनती किसानों को जारी की जाएगी। इस शिखर सज़्मेलन का उद्देश्य भारत के कृषि भविष्य के लिए एक व्यवहार्य, जलवायु-अनुकूल और आर्थिक रूप से टिकाऊ मॉडल के रूप में प्राकृतिक और पुनर्योजी खेती की ओर बदलाव को गति देना भी है।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है, शिखर सज़्मेलन में किसान-उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाज़ार संपर्क बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही जैविक आदानों, कृषि-प्रसंस्करण, पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग और स्वदेशी तकनीकों में नवाचारों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

इस शिखर समेलन में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 50,000 से अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसायी, वैज्ञानिक, जैविक आदान आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक भाग लेंगे।

जगन मोहन रेड्डी हैदराबाद में सीबीआई अदालत में पेश

अमरावती २०/११ (संवाददाता): आंध्र प्रदेश के पूर्व मुज़्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी करीब छह साल बाद कथित अवैध लेन-देन संबंधी मामले की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुये। वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफमुकदमा लंबित है, जिसमें कथित अवैध लेन -देन मामले में वह मुज़्य आरोपी हैं।

जगन के खिलाफ 11 आरोप पत्र दायर हैं। ये मामले अलग-अलग कंपनियों द्वारा उनकी फर्मों में किए गए निवेश से जुड़े हैं, जो उनके पिता स्वर्गीय वाई एस राजशेखर रेड्डी के 2004 से 2009 के बीच अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुज़्यमंत्री रहने के दौरान उन्हें दिए गए अलग-अलग फायदों के बदले में किए गए थे।

अदालत ने पहले रेड्डी को यूरोप दौरे से लौटने के बाद 14 नवंबर को खुद पेश होने का निर्देश दिया था। लेकिन, उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए एक याचिका दायर की थी और कहा था कि वह आनलाइन माध्यम से पेश होंगे।

सीबीआई के लोक अभियोजक इंद्रजीत संतोषी ने मामले पर बहस करते हुए इसका विरोध किया और कहा कि अदालत के पिछले आदेश के मुताबिक रेड्डी का पेश होना ज़रूरी है और उन्हें इसका पालन करना चाहिए। इसके बाद, अदालत ने आदेश दिया कि रेड्डी को 21 नवंबर तक खुद कार्यवाही में शामिल होना होगा।

अदालती आदेश का पालन करते हुए, रेड्डी बृहस्पतिवार को अदालत के सामने पेश हुए और इन मामलों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रेड्डी के पेश होने को देखते हुए, अदालत परिसर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

पिछली बार रेड्डी जब जनवरी 2020 में सीबीआई की अदालत में खुद पेश हुए थे, तब वह मुज़्यमंत्री थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले रेड्डी को इन मामलों के सिलसिले में सीबीआईअदालत में खुद पेश होने से छूट दी थी।

नीतीश के 10वीं बार सीएम बनने पर पवन खेड़ा का तंज-धोखा न मिले, कार्यकाल पूरा करें

नयी दिल्ली २०/११ (संवाददाता): बिहार के मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार को रिकॉर्ड 10वीं बार पद की शपथ लेने पर बधाई देते हुए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को उन पर कटाक्ष किया और उज़्मीद जताई कि उन्हें कोई धोखा नहीं सहना पड़ेगा और वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। एएनआई से बात करते हुए, खेड़ा ने नीतीश कुमार और बिहार में एनडीए से अपने चुनावी वादे पूरे करने को कहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं और उज़्मीद करते हैं कि उन्हें कोई धोखा नहीं सहना पड़ेगा और वे अपना कार्यकाल पूरा कर पाएँगे। कम से कम वे कुछ ऐसा तो कर पाएँ जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ। बिहार में वे चाहे जैसे भी जीते, उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए।इससे पहले आज, जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुज़्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ, जहाँ 2005, 2010 और 2015 में उनके शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो चुके हैं। यहीं पर जयप्रकाश नारायण ने 1974 में अपने भाषण में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। हरियाणा के मुज़्यमंत्री नायब सिंह सैनी, असम के मुज़्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, नागालैंड के मुज़्यमंत्री नेज़्यू रियो, आंध्र प्रदेश के मुज़्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उज़र प्रदेश के मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उज़राखंड के मुज़्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहज़्मद खान और लोजपा (रालोद) प्रमुख चिराग पासवान सहित अन्य लोग गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

राम मंदिर के शिखर पर मोदी के हाथों फहराएगा भव्य भगवा ध्वज, 25 नवंबर को विशेष आयोजन

नयी दिल्ली २०/११ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उज़र प्रदेश के मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 25 नवंबर को 8,000 से अधिक मेहमानों की उपस्थिति में राम मंदिर के ऊपर विशेष रूप से डिजाइन किया गया भगवा ध्वज फहराएंगे। 25 नवंबर को राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के दिन, केवल आमंत्रित अतिथि ही रामलला के दर्शन कर पाएँगे। 25 नवंबर को आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे। हालांकि, 26 नवंबर को सुबह 4 बजे से श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन शुरू हो जाएँगे।

कल मुज़्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ एक बैठक में, प्रशासनिक अधिकारियों ने यह जानकारी इस सवाल के जवाब में दी कि वे %राम विवाह% के अवसर पर अयोध्या में आने वाले बड़ी संज़्या में राम भक्तों को दर्शन की अनुमति कब देंगे।

यह पहली बार होगा जब राम मंदिर में राम-सीता विवाह उत्सव मनाया जाएगा। ध्वजारोहण समारोह और राम विवाह समारोह एक ही दिन होने के कारण, अयोध्या में श्रद्धालुओं की संज़्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक होगी। अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टी. फंडे ने बुधवार को यहाँ बताया कि राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह से एक दिन पहले आने वाले मेहमानों को 24 नवंबर को दर्शन की अनुमति दी जाएगी।

श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि कुल मिलाकर, सात झंडे होंगे, एक मुज़्य मंदिर के गुंबद के लिए और बाकी छह अन्य मंदिरों के लिए... सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, हमें विशेष रूप से बताया गया था कि मंदिर में आने वाले सभी आम लोगों के साथ सुरक्षाकर्मियों द्वारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए... कार्यक्रम के दिन, लगभग 15 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई परेशानी न हो, ज़्योंकि भीड़ प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था की गई है... प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राज्य के राज्यपाल भी होंगे।

उनके साथ, लगभग 7,000 वीआईपी मेहमानों के आने की उज़्मीद है। उनके ठहरने के साथ-साथ उनके मंदिर दर्शन के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है।

मिश्र ने बताया कि राम बारात और उससे जुड़े कार्यक्रमों में किसी भी तरह की असुविधा न हो इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उनके मुताबिक, आगामी 26 नवंबर को बड़ी संज़्या में श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन की सुविधा उपलज़्ध कराने के लिये रामलला का गर्भगृह 16 घंटे से ज़्यादासमय तक खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कर्मचारियों को तीर्थयात्रियों के साथ व्यवस्थित और विनम्र व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये हैं। मिश्र ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि मुज़्य मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाने के लिए तकनीकी और हस्तगत दोनों ही प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया है। उनके मुताबिक, परिसर के सातों मंदिरों के ध्वज त्रिकोणीय होंगे और उन पर केवल ओम का चिह्न होगा और वे मुज़्य मंदिर के ध्वज से छोटे होंगे। उन्होंने बताया कि ध्वजारोहण के दो सफल परीक्षण पहले ही पूरे हो चुके हैं तथा सभी मंदिरों के शिखरों पर लगे ध्वज स्थायी रहेंगे और उन्हें वर्ष में केवल एक या दो बार ही बदलने के लिए उतारा जाएगा।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

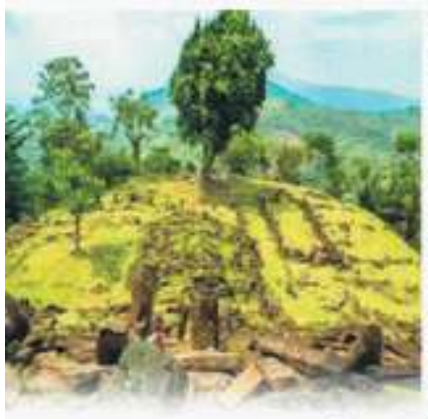

16,000 साल से अधिक पुराना है दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड

गुनुंग पदांग

आर्कियोलॉजिस्ट्स ने 'दुनिया का सबसे पुराना' पिरामिड खोजा है, जो इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा द्वीप पर लावा की पहाड़ी के भीतर 98 फीट गहरा बना हुआ है. पता चला है कि जिसकी गहराई अंडरग्राउंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितनी है. इसका नाम गुनुंग पदांग पिरामिड है. इसकी कार्बन-डेटिंग से पता चलता है कि यह 16,000 साल से अधिक पुराना है.

कब खोजा गया था ये पिरामिड

रिपोर्ट के अनुसार, गुनुंग पदांग पिरामिड को पहली बार 1890 में डच खोजकर्ताओं ने खोजा था. इस प्राचीन जगह की हालिया रेडियोकार्बन डेटिंग जांच से चौंकाने वाले जानकारी निकल कर सामने आई है. पता चला है कि यह कम से कम अपने आकार का सबसे पुराना ज्ञात मानव निर्मित निर्माण भी हो सकती है.

कितना पुराना है ये पिरामिड?

परीक्षणों में पिरामिड के शुरुआती निर्माण का भी पता चला है, जिसमें सीढ़ियां एंडेसाइट लावा से तराशी गई थीं, जो 16 हजार साल से भी पहले आखिरी हिमयुग के दौरान बनाई गई थी. इसका मतलब यह है कि गुनुंग पदांग पिरामिड न केवल मिस्र में गीजा के सभी महान स्मारकों और पिरामिडों से, बल्कि इंग्लैंड के स्टोनहेंज से भी 10,000 साल पुराना है.

किससे बना है ये पिरामिड?

रिसर्चर्स ने पाया कि इंडोनेशियाई पिरामिड की पहली और सबसे गहरी परत साइट के ठंडे लावा प्रवाह से बनाई गई थी. गुनुंग पडांग पिरामिड तुर्की में खोजे गए गोबेकली टेपे 'मेगालिथ' से भी हजारों साल पुराना साबित हो सकता है, जो 'दुनिया के सबसे पुराने' आर्कियोलॉजिकल साइट की दौड़ में आखिर स्थान पर है.

कैसी है इस पिरामिड की सरंचना?

इस प्राचीन पिरामिड की सरंचना के रहस्य की तह तक जाने में साइंटिस्ट्स जुटे हुए हैं. इसके लिए उन्होंने सब-सरफेस इमेजेज, कोर ड्रिलिंग और 'ट्रेंच' उत्खनन जैसी आधुनिक टेक्निक्स का सहारा लिया है. जिससे रिसर्चर्स गुनुंग पदांग पिरामिड की सरंचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. उनको पिरामिड की परतों के बारे में पता चला है, जो इसकी सतह से 9 मंजिल नीचे (98 फीट या 30 मीटर) तक फैली हुई थीं.

एक सींग वाले एशियाई गैंडे के लिए प्रसिद्ध है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान

80 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध पार्क पर्णपाती जंगलों से भरा हुआ है जो वनस्पतियों और जीवों की विस्तृत श्रंखला का दावा करता है। यह राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से अपने एशियाई एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसके अलावा राजसी एशियाई हाथी, शाही बंगाल टाइगर और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भारतीय जंगली कुत्ते, विशालकाय गिलहरी, जंगली सूअर, हिरण, कोबरा, अजगर, कठफोड़वा और कई अन्य प्रजातियों को भी यहाँ आसानी से देखा जा सकता है।

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मूर्ति और रैदक नदियों के तट पर स्थित पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। 80 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ यह प्रसिद्ध पार्क पर्णपाती जंगलों से भरा हुआ है जो वनस्पतियों और जीवों की विस्तृत श्रंखला का दावा करता है। यह राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से अपने एशियाई एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसके अलावा राजसी एशियाई हाथी, शाही बंगाल टाइगर और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भारतीय जंगली कुत्ते, विशालकाय गिलहरी, जंगली सूअर, हिरण, कोबरा, अजगर, कठफोड़वा और कई अन्य प्रजातियों को भी यहाँ आसानी से देखा जा सकता है। अपनी शानदार सुंदरता और वनस्पतियों और जीवों की समृद्धि के कारण, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पिछले एक दशक में एक उभरते हुए लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है जो हर साल कई हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटकों की मेजबानी करता है।

1895 से एक आरक्षित वन होने के कारण गोरुमारा को 1949 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था जिसे भारतीय गैंडों की प्रजनन आबादी के कारण 31 जनवरी 1994 को एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आधिकारिक दर्जा दिया गया था। मूल रूप से यह पार्क 7 वर्ग किलोमीटर छोटा था जिसे पड़ोसी भूमि को लगभग 80 वर्ग किलोमीटर शामिल करके विकसित गया है। जिस क्षेत्र में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उसे डूअर्स के नाम से जाना जाता है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह स्थान प्राकृतिक और प्राचीन सौंदर्य से भरपूर है। पार्क अपनी पर्वत श्रृंखलाओं और झरनों के साथ बिल्कुल आश्चर्यजनक लगता है। अधिकांश जंगल नम पर्णपाती है। हालांकि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य वनस्पति साल है; सागौन, सिल्क कॉटन (सिमुल), रेन ट्री (शिरीष) और खैर भी यहाँ पाए जा सकते हैं साथ ही यहां कई तरह के ऑर्किड और फर्न भी देखे जा सकते हैं।

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और कीड़ों की कई प्रजातियों का घर है जो सबसे जाहिरा एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए सबसे प्रसिद्ध है। यहां आमतौर पर पाए जाने वाले अन्य जानवरों में तेंदुए, हाथी, भारतीय बाइसन, रॉक पायथन, हिरण और मलायन विशालकाय गिलहरी शामिल हैं। कुल मिलाकर, पार्क में मांसाहारी और शाकाहारी जीवों की लगभग 48 प्रजातियां हैं। पार्क पक्षियों की 193 प्रजातियों, सरीसृपों की 22 प्रजातियों, कछुओं की 7 प्रजातियों और मछलियों की 27 प्रजातियों का निवास स्थान भी है। मिनिवेट्स, तीतर, हॉर्नबिल, कठफोड़वा, कोयल, कबूतर और मैना कुछ ऐसे पक्षी हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यहां चैती, सारस और आइबिस जैसे प्रवासी पक्षी भी देखे जा सकते हैं।

खासकर सुबह या देर दोपहर की सफारी के दौरान।

गोरुमारा नेशनल पार्क सफारी

सफारी राइड गोरुमारा नेशनल पार्क में सबसे प्रसिद्ध और मजेदार गतिविधि वन्यजीव सफारी है जिसकी बिना पार्क की यात्रा कभी पूरी नहीं होती है। इन सफारी के दौरान आप दूर से ही कई जानवरों, पक्षियों और पार्क की सुंदरता और भव्यता को देख सकते हैं। आप जब भी यहाँ आयेंगें तो दो प्रकार की सफ़ारी चुन सकते है– हाथी सफारी और जीप सफारी, जो वन्यजीवों को देखने की गारंटी देती है। आप वन विभाग से अपनी वन सफारी बुक कर सकते हैं और गोरुमारा नेशनल पार्क की ट्रिप को एन्जॉय कर सकते है।

मेथला वॉचटावर

यह वॉचटावर राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी किनारे की ओर कालीपुर इको गांव में स्थित है। यहां अद्वितीय बैलगाड़ी चालित सफारी उपलब्ध हैं जो पर्यटकों को काफी आकर्षित और मनोरंजित करती है।

चंदचूर वॉचटावर

यह वॉचटावर विशाल और खुले घास के मैदान के बीच में स्थित है। यहां एक छोटा तालाब और नमक की झील भी है।

गोरुमारा नेशनल पार्क में घूमने की जगहें

यदि आप गोरुमारा नेशनल पार्क की यात्रा को प्लान कर रहे हैं तो हम आपको बता दे गोरुमारा नेशनल पार्क में विभिन्न वन्यजीवों के अलावा आप अन्य कई प्रसिद्ध जगहें भी हैं जिन्हें देखने के लिए जा सकते है।

जात्राप्रसाद

जात्राप्रसाद वॉच टॉवर गोरुमारा नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध लुकआउट है, और इसका नाम एक मादा हाथी के नाम पर रखा गया है जो अपनी देखभाल करने वाले स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। इस प्रहरीदुर्ग का प्रवेश बिंदु राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से है। वॉचटावर के ठीक नीचे नमक की झीलें इसे वन्यजीवों को देखने के लिए एक आकर्षक जगह बनाती है.

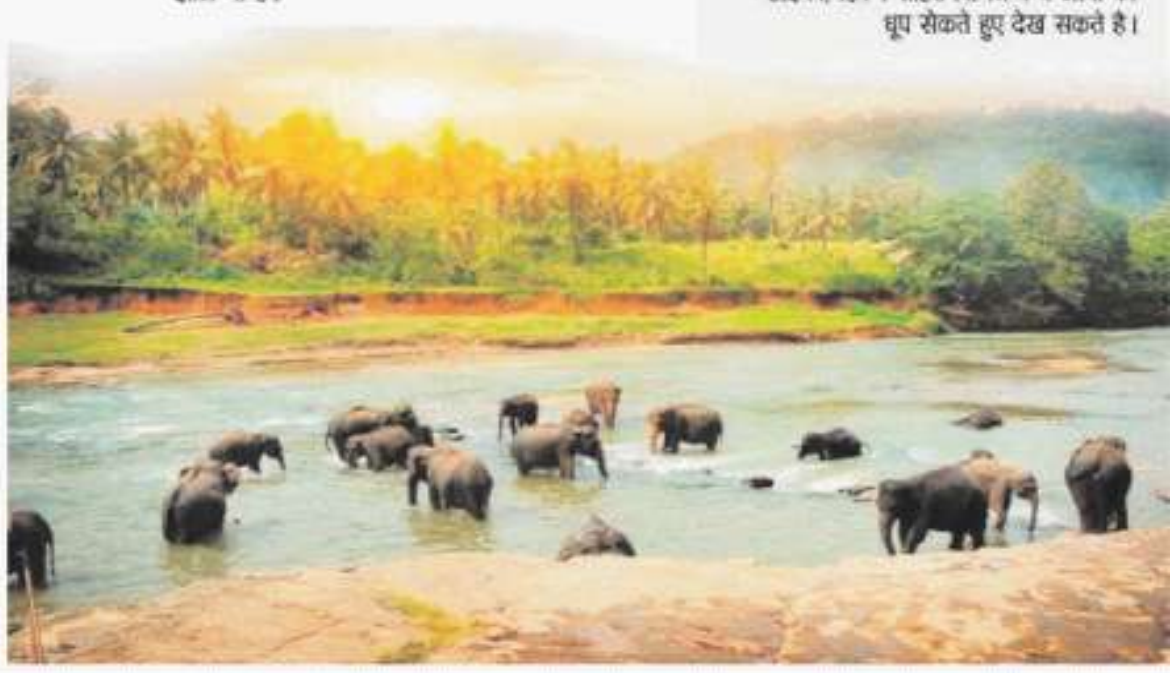

गोरुमारा नेशनल पार्क की यात्रा के लिए टिप्स

यदि आप गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा पर जाने वाले है, तो किसी भी दुर्घटना और परेशानी से बचने के लिए नीचे दिए इन टिप्स को अपनी यात्रा के दौरान अवश्य फोलो करें –

- गोरुमारा नेशनल पार्क की यात्रा पर जाने से पहले रूम और सफारी की बुकिंग अवश्य कर ले, क्योंकि पीक सीजन में कभी कभी सफारी और होटल्स की तुरंत बुकिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो आपकी यात्रा को प्रभावित कर सकते है।
- अपनी ट्रिप में चमकीले रंगों के कपड़े न पहनें क्योंकि यह खतरनाक जानवरों को आकर्षित कर सकता है।
- पार्क के किसी प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश ना करें
- सफारी राइड में अपने गाइड की परमिशन के बिना जीप से बाहर ना निकलें।
- गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा में कैमरा, दूरबीन,सनग्लासेस और अन्य आवश्यक चीजें जरूर साथ रखें।
- पार्क में किसी भी जानवर को खिलाने या उनके पास जाने की कोशिश ना करें।

बता दे गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा में स्मोकिंग बिलकुल ना करें, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा बना रहता है।

गोरुमारा नेशनल पार्क घूमने जाने का बेस्ट टाइम

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के घूमने के लिए 15 जून से 15 सितंबर तक बंद रहता है। लेकिन यदि हम गोरुमारा नेशनल पार्क घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय की बात करे, तो अक्टूबर से अप्रैल गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि सर्दियों का समय ऐसा समय होता है, जब गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में आप बंगाल टाइगर, हिरण सहित विभिन्न वन्य जीवो को धूप सेकते हुए देख सकते है।

शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास स्थित है। 3590 मीटर की ऊंचाई वाली यह झील पहलगाम से कुल 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित अमरनाथ गुफा तक जाती है। इसलिए जो यात्री अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वे शेषनाग झील भी जाते हैं। झील की लंबाई 1.1 किमी और चौड़ाई 1.7 किमी है। झील का नाम शेषनाग के नाम पर रखा गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका अर्थ होता है दिव्य नाग या नागों का राजा। ऐसा कहा जाता है कि खुद नाग ने ही इस झील को खोदा था और यहीं अपना निवास स्थान बना लिया।

अमरनाथ गुफा तक जाती है 3590 मीटर की ऊंचाई वाली शेषनाग झील

शेषनाग को कई बार 5 सिर के साथ देखा गया है तो कई बार छह, सात और सौ सिरों के साथ। पर हिन्दू धर्म में शेषनाग के सात सिर ही माने जाते है। शेषनाग झील को प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह अमरनाथ गुफा के तीर्थ मार्ग पर स्थित है। इस झील के प्राकृतिक परिवेश में हरेभरे चरागाह और बर्फ से ढके पहाड़ पर्यटकों को मोहित कर देते हैं। चंदनवारी से ऊपर की ओर जाने वाली ट्रेक या टट्टू की सवारी द्वारा इस झील तक पहुंचा जा सकता है। खास बात यह है कि सर्दियों में यह झील जम जाती है और गर्मियों के दौरान झील का पानी आमतौर पर ठंडा रहता है। यह झील देश के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल सैकड़ों भक्त आते हैं। 250 फीट गहरी इस झील की कोई तारीख उल्लेखित नहीं है, लेकिन शेषनाग कई हजार सालों से अस्तित्व में है।

कौन हैं शेषनाग

शेषनाग का अर्थ सांपों के राजा से है। इसके अलावा शेषनाग भगवान विष्णु का सिंहासन भी है। शेषनाग एक बड़ा सिर वाला नाग है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में नागों के राजा के रूप में जाना जाता है। मिथक के अनुसार ब्रह्मांड के सभी ग्रह नाग के सिर पर होते हैं और हर बार जब वह पृथ्वी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है तो भूकंप आता है। अमरनाथ जाने वाले सभी भक्त शेषनाग झील जरूर जाते है। साइंस के अनुसार यह झील बहुत अल्पपोशी है। अल्पपोशी का अर्थ है कम पोशक तत्वों का होना, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा में इजाफा होता है। इसी वजह से इस झील का पानी काफी साफ और उपयोग करने वाला है। पर्यटक झील के पानी में ट्राउट मछलियों को देख सकते हैं, ये ऐसी मछलियां होती हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

शेषनाग झील की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव देवी पार्वती को अमरकथा सुनाने के लिए अमरनाथ से जा रहे थे। वे चाहते थे कि इस कथा को कोई न सुने। क्योंकि जो इस कथा को सुनेगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने अनंत सांपों –नागों को अनंतनाग में वेल नंदी को पहलगाम में और चंद्रमा को चंदनवाड़ी में ही छोड़ गए थे। लेकिन शेषनाग उनके साथ गया था, जिसे उन्होंने इस झील में छोड़ दिया था। ताकि कोई इस झील को पार कर आगे न जा पाए। यही वजह है कि झील का नाम शेषनाग पड़ गया। दूसरी कथा यह है कि शेषनाग ने खुद इस जगह को खोदा और यहां रहने लगे। यहां के निवासियों का तो यह भी कहना है कि शेषनाग आज भी यहां रहते हैं और आज भी इस झील को कोई पार नहीं कर सकता।

शेषनाग झील का रहस्य

शेषनाग झील से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है, जिससे सुनने के बाद हर कोई अचंभित हो जाता है। इस झील में घटने वाली एक घटना सदियों से हो रही है। यहां के स्थानीय लोगों में इस झील के प्रति गहरी आस्था और विश्वास है। झील के बारे में बताया जाता है कि इस झील में शेषनाग निवास करते हैं। 24 घंटों में एक बार खुशनसीबियों को ही शेषनाग के अद्भुत दर्शन होते हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस झील में शेषनाग की आकृति साफ झलकती है। ये आकृति पानी पर उभरकर आती है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ यहां जमा हो जाती है। हर साल हजारों लोग शेषनाग की आकृति को देखने के मकसद से यहां पहुंचते हैं।

कलिंग समाचार

संपादकीय

शुक्रवार 21 नवंबर 2025

संविधान से बड़ी छेड़छाड़ का रास्ता खुला

अपनी सं या बल के आधार पर चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक एलांयस (एनडीए) की सरकार ने देश के वक्फ़ कानून में अपनी मर्जी का बदलाव करने में सफलता पा ली हो, लेकिन जो संदेश इसे पारित करने के लिये, खासकर लोकसभा में हुए मतदान ने जनता को दिया है उससे स भवत: देश के अल्पसं यकों को यह जानने में मदद मिलेगी कि उनकी जगह क्या है, उनके खैर वाह कौन हैं और कौन अहित चाहते हैं। लोकसभा ने बुधवार को 288 के मुकाबले 232 वोटों के बहुमत से वक्फ़ संशोधन विधेयक, 2024 को पारित कर दिया तथा गुरुवार को राज्यसभा में दिन भर से इस पर चर्चा जारी है। इस सदन में 236 सदस्य हैं। बिल को पास करने के लिये 119 सदस्य चाहिये जबकि भाजपा के इसमें 98 सदस्य हैं। लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में विरोधी खेमे के 5 सदस्यों के वोट पड़े थे। राज्यसभा में भाजपा आवश्यक आंकड़ा प्राप्त करती है या नहीं, यह देखना होगा। हालांकि इस सदन में प्रस्ताव गिर भी जाये तो भी सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद में उसे दोबारा भेजकर संवैधानिक नियमों के तहत पारित करा ही लिया जायेगा। इसे उच्च सदन पूरी तरह से रोक नहीं पायेगा। इस कानून के एक तरह से अस्तित्व में आ जाने के बाद अब वक्त है कि अल्पसं यक, विशेषकर मुस्लिम सोचें कि उन्हें आगे क्या करना है। यह ऐसा समय है जब उन्हें समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल और व्यक्ति उनका वाकई भला चाहते हैं और किन दलों ने इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग देकर उन्हें कमजोर करने का मार्ग प्रशस्त किया है। वैसे तो मतदान का जो पैटर्न दिखा तथा विधेयक के पक्ष-विपक्ष में जो तर्क दिये गये, वे बता देते हैं कि कौन सा दल उनके पक्ष में खड़ा है। कोई यह न सोचे कि यह पैटर्न वक्फ़ कानून पर मतदान तक ही सीमित रहेगा। पहली बार 8 अगस्त, 2024 को जब यह विधेयक संसद में पेश हुआ था, तब उस पर हुई चर्चा, तत्पश्चात उसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजे जाने तक कुछ दलों का रवैया आश्चर्यजनक ढंग से तथा उ मीदों के विपरीत भाजपा के प्रति सहयोगात्मक रहा। ये वे दल हैं जो वक्फ़ कानून पर सरकार से बात कर सकते थे। इनमें से कम से कम दो तो ऐसी पार्टियां हैं ही जो अल्पसं यकों के हितों की रक्षक मानी जाती रही हैं और उन्हीं पर सरकार टिकी हुई है। यदि एक बार भी वे समर्थन वापसी की धमकी देते तो यह विधेयक भाजपा सरकार अलमारी में बन्द कर देती। ये दोनों दल हैं- आंध्रप्रदेश की तेलुगु देसम पार्टी और बिहार की जनता दल यूनाइटेड जिसके क्रमश: 16 और 12 सदस्य हैं। दोनों ही अल्पसं यक समर्थक पार्टियां कहलाती हैं लेकिन इस विधेयक को उनके मिले समर्थन ने यह भरम तोड़ दिया। इस विधेयक पर चर्चा ने सियासी समीकरणों को तथा सत्ता के लिये विचारधारा की कुर्बानियों को और भी स्पष्ट कर दिया है। इस कानून को पारित कराकर भाजपा यह बताने में कामयाब रही है कि इस लोकसभा के चुनाव में उसे चाहे कम सीटें मिली हों लेकिन जनता अब भी उसके साथ है तथा एनडीए को कोई खतरा नहीं है। जेडीयू व टीडीपी के सांसदों के अलावा राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी एवं जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चिराग पासवान से भी अल्पसं यकों व धर्मनिरपेक्षता में यकीन करने वालों को उ मीद थी कि वे उनके पक्ष वाली लाइन पर चलेंगे लेकिन वे भी सरकार के साथ रहे। इनमें से कई मंत्री व सांसद तो अपने भाषणों में भाजपा ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी मात देते हुए नज़र आये। कोई यह न समझे कि संदेश केवल अल्पसं यकों से स बन्धित इस विधेयक तक ही सीमित है। यही हाल दलितों व ओबीसी से स बन्धित किसी भी फैसले के वक्त होगा- फिर चाहे वह उनके खिलाफ ही क्यों न हो। यह अवसर न केवल अल्पसं यकों को राजनीतिक विचारधारा तथा सियासी दलों के साथ अपनी प्रतिबद्धता पर पुनर्विचार करने का है, बल्कि दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के बारे में यह कहा जा सकता है।

न्यायपालिका को सरकार की बांदी बनाने की मुहिम

अनिल जैन

यह सही है कि संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि विधानसभा में पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को कितने समय के अंदर मंजूरी देनी है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयक को बिना मंजूरी दिए अपने पास रख सकते हैं। अगर कोई राज्यपाल ऐसा करता है तो जाहिर है कि वह अपनी सरकार को काम नहीं करने देना चाहता है।

इस समय केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह गाली-गलौज की भाषा में धमकाया जा रहा है, उसे देखते हुए करीब चार दशक पुराना वाकया याद आ रहा है। उस समय राजीव गांधी की सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे- बिहार के कमलाकांत तिवारी उर्फ के.के. तिवारी। वे अपने नाम के साथ %प्रोफेसर% भी लिखते थे, जिससे ऐसा लगता था कि वे पढ़े-लिखे और शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी काबिलियत यह थी कि वे अव्वल दर्जे के चापलूस, बदतमीज, बदजुबान थे।

राजीव गांधी और उनकी सरकार के खिलाफ बोलने-लिखने वाले किसी भी विपक्षी नेता या किसी बड़े पत्रकार के खिलाफ़ गाली-गलौज करने और उसका रिश्ता सीआईए या केजीबी से जोड़ने में के.के. तिवारी बिलकुल देर नहीं लगाते थे। इस सिलसिले में उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तक को नहीं ब .शा था। उन्होंने जैल सिंह के संबंध पंजाब के आतंकवादियों से जोड़ते हुए राष्ट्रपति भवन को साजिशों का अड्डा तक बता दिया था। हालांकि तिवारी को अपनी बदजुबानी की कीमत मंत्री पद से इस्तीफा देकर चुकानी पड़ी थी। उसके कुछ समय बाद हुए चुनाव में कांग्रेस भी सत्ता से बाहर हो गई थी। के.के. तिवारी का क्या हुआ, वे कहां हैं या नहीं हैं, किसी को नहीं मालूम।

बहरहाल नरेन्द्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव के हालात बना रखे हैं। राजीव गांधी के पास तो एक ही के.के. तिवारी थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पास के.के. तिवारीनुमा मंत्रियों और सांसदों की एक बड़ी फौज है जिसने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हैरानी की बात यह है कि उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस फौज की अगुवाई करते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले टकराव का मुद्दा बने हुए हैं। एक फैसले में राज्यपालों की मनमानी पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य विधानसभा में पारित विधेयक को राज्यपाल अनंतकाल तक बिना मंजूरी दिए अपने पास नहीं रख सकेंगे। अगर राज्यपाल किसी विधेयक को खुद मंजूरी न देते हुए उसे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को भी उस पर तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा।

यह सही है कि संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि विधानसभा में पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को कितने समय के अंदर मंजूरी देनी है।

इसका यह मतलब भी नहीं है कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयक को बिना मंजूरी दिए अपने पास रख सकते हैं। अगर कोई राज्यपाल ऐसा करता है तो जाहिर है कि वह अपनी सरकार को काम नहीं करने देना चाहता है। आजादी के बाद लंबे समय तक इस मामले मे सुधार की जरूरत महसूस नहीं हुई या सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो उसका कारण यह था कि किसी भी राज्यपाल ने महीनों और सालों तक विधेयक लटका कर नहीं रखे। यह समस्या अभी हाल के वर्षों में ही पैदा हुई है।

हालांकि जिन राज्यों में भाजपा या उसके गठबंधन की सरकारें हैं, वहां इस तरह की कोई समस्या नहीं है, परन्तु गैर भाजपा शासित लगभग सभी राज्यों में राज्यपालों ने अघोषित रूप से यह रवायत बना ली है कि वे सरकार को परेशान करने की नीयत से विधेयकों को लटकाए रखते हैं और कभी-कभी विधेयक को विवादास्पद बताकर उसे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। राष्ट्रपति के पास भी वह विधेयक महीनों तक पड़ा रहता है। ऐसी ही समस्या का निदान करने के लिए ही तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और विधेयकों की मंजूरी के लिए एक समय सीमा निश्चित करनी पड़ी।

यह फैसला आते ही उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार के मंत्री बिफर पड़े और अमर्यादित भाषा में सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्यादा में रहने की नसीहत देने लगे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज लोगों को यह नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट को यह दखल क्यों देना पड़ा। उपराष्ट्रपति धनखड़ तो संवैधानिक मामलों के जानकार बताए जाते हैं। जाहिर है कि उन्हें राज्यपालों की बदनीयती और मनमानी पर संवैधानिक अंकुश मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से सरकार के टकराव का दूसरा मामला तो और भी ज्यादा संगीन स्थिति में पहुंच गया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ़ संशोधन के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश आते ही भाजपा नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पर हमले शुरू हो गए हैं।

यह फैसला आते ही उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार के मंत्री बिफर पड़े और अमर्यादित भाषा में सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्यादा में रहने की नसीहत देने लगे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज लोगों को यह नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट को यह दखल क्यों देना पड़ा। उपराष्ट्रपति धनखड़ तो संवैधानिक मामलों के जानकार बताए जाते हैं। जाहिर है कि उन्हें राज्यपालों की बदनीयती और मनमानी पर संवैधानिक अंकुश मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से सरकार के टकराव का दूसरा मामला तो और भी ज्यादा संगीन स्थिति में पहुंच गया है।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, भारत में चल रहे गृह युद्धों के लिए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना जि मेदार हैं।% इस सिलसिले में दुबे ने अपनी जहरीली जुबान से देश के पूर्व मु य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को भी निशाना बनाया। वक्फ़ संशोधन कानून को लेकर कुरैशी की एक पोस्ट के जवाब में दुबे ने कहा कि %आप मु य चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे।%

देश के प्रधान न्यायाधीश पर दुबे के आपत्तिजनक और खतरनाक बयान के बाद भाजपा के दूसरे कई सांसदों और नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट को अपनी हदों में रहने की नसीहत दी। हालांकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे और अन्य नेताओं के बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनके बयानों से पार्टी सहमत नहीं है, ये उनके निजी बयान हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी न्यायपालिका के खिलाफ ऐसी बातों को नापसंद करती है। उनकी इस सफाई से समझा गया कि भाजपा ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मगर इसके बाद भाजपा के अंदर से जैसी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उनसे विवाद में नया पहलू जुड़ा है। दो प्रतिनिधि बयान खास तौर पर गौरतलब हैं= पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने निशिकांत दुबे की बातों को दोहराते हुए कहा कि- %उन्होंने सही बात कही है।% भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दुबे को %सार्वजनिक रूप% से ऐसी बातें न बोलने की सलाह देते हुए कहा-%कभी-कभी सच बोलने से बचना पड़ता है।%

सत्ताधारी जमात के इकोसिस्टम के एक हिस्से ने तो सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ नड्डा को भी निशाने पर ले लिया। उनके खिलाफ अपमानजनक हैशटैग ट्रैंड कराया गया, जिसके तहत कुछ लोगों ने उनसे इस्तीफ़े की मांग भी की। इससे विपक्ष के इस आरोप को वजन मिला कि दुबे ने जो कहा, वह सत्ताधारी जमात की असल मंशा को जाहिर करता है और नड्डा की सफाई महज रस्म अदायगी है। वक्फ़ संशोधन विधेयक का पारित कराना, उस पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक को लेकर निशिकांत दुबे का बयान तथा राज्यपालों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ सहित तमाम भाजपा नेताओं के बयान भाजपा एवं उसकी सरकार की एक सोची-समझी रणनीति के हिस्से हैं।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट को ऐसी नसीहतें देने और सरकार व संसद को उससे ऊपर बताने का सिलसिला बहुत पहले से जारी है। कानून मंत्री रहते हुए रविशंकर प्रसाद कई मौकों पर ऐसी नसीहत दे चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तो केरल के सबरीमाला मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर 27 अक्टूबर 2018 को साफ शब्दों में कहा था- अदालतें किसी मामले में फैसला देते वक्त व्यावहारिक रुख अपनाएं और वैसे ही फैसले दें, जिन पर अमल किया जा सके।

दरअसल संसद, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां और मीडिया को अपने अनुकूल बनाने के बाद अब न्यायपालिका ही ऐसी संस्था बची है जो पूरी तरह सरकार के काबू में नहीं आ पाई है। सो, उसे काबू में करने का अभियान छेड़ दिया गया है। सहयोगी दलों की बैसाखियों पर टिकी 240 लोकसभा सीटों वाली सरकार का यह दुस्साहस देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लोकसभा चुनाव में 400 सीटें क्यों चाहिए थीं और अगर वे मिल जातीं तो क्या होता!

भाषा के मुद्दे पर तमिलनाडु का केंद्र के साथ टकराव बहुत दूर तक चला गया

कल्याणी शंकर

सरकार ने तमिल शब्द रुबाइ के पहले अक्षर श्रुश् के साथ एक लोगो जारी किया‌ए जिसका अर्थ है मुद्रा। लोगो में कैप्शन है श्सब कुछ सबके लिए।श् इसका उद्देश्य समावेशिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाना है और इसका उद्देश्य अपनी विविध आबादी के बीच एकता बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ;एनईपीद्ध के तहत तीन.भाषा सूत्र पर असहमति और बढ़ गयी हैए खासकर भाषा को लेकर।

गुरुवार कोए तमिलनाडु ने अपने बजट दस्तावेज़ में आधिकारिक रुपये के प्रतीक;घ्द्ध को तमिल अक्षर से ;घ्द्ध बदलकर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन किया। उच्चारितए यह अक्षर तमिल भाषा में भारतीय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है और इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। मु यमंत्री स्टालिन के प्रतीक को बदलने के फैसले का वैश्विक प्रभाव पर व्यापक असर हो सकता है। रुपया भारत की संप्रभुता के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक ;डीएमकेद्धइसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ;एनईपीद्ध के खिलाफ एक साहसिक और निर्णायक कदम उठाते हुएए तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 2025 के बजट में आधिकारिक रुपये के प्रतीक ;घ्द्ध को तमिल वर्ण से बदल दिया। मु यमंत्री एमण्केण् स्टालिन की घोषणा कि राज्य के 2025.26 के बजट लोगो में रुपये के प्रतीक का उपयोग किया जायेगाए इस निर्णय के महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करता है। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके भाषा के मुद्दों सहित कई मुद्दों पर केन्द्र से साथ टकराव की स्थिति में है। सोशल मीडिया एक्स पर हाल ही में एक पोस्ट मेंए स्टालिन ने नये लोगो का एक टीज़र वीडियो साझा किया। इसमें हैशटैगद्रविडियन मॉडल और टीएन बजट.2025 के साथ लिखा थाए श्तमिलनाडु के व्यापक विकास को सुनिश्चित करना और समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना।श् लोगो में च्सब कुछ सबके लिएश् भी लिखा थाए जो स्पष्ट रूप से समावेशी शासन के लिए डीएमके की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने तमिल शब्द रुबाई के पहले अक्षर श्रुश् के साथ एक लोगो जारी किया‌ए जिसका अर्थ है मुद्रा। लोगो में कैप्शन है श्सब कुछ सबके लिए।श् इसका उद्देश्य समावेशिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाना है और इसका उद्देश्य अपनी विविध आबादी के बीच एकता बनाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ;एनईपीद्ध के तहत तीन.भाषा सूत्र पर असहमति और बढ़ गयी है। नया विवाद तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को और बढ़ाता हैए खासकर भाषा को लेकर। तमिलनाडु ने केंद्र के त्रि.भाषा फॉर्मूला का विरोध किया हैए तथा यह जोर देकर कहता है कि तमिलनाडु अपना द्वि.भाषा फॉर्मूला जारी रखेगा। डीएमके का कहना है कि तमिलनाडु ब्रिटिश उपनिवेशवाद के स्थान पर अब हिंदी उपनिवेशवाद को स्वीकार नहीं करेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर बेईमान होने और राजनीतिक कारणों से छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाती है।

अपने बजट दस्तावेज़ में तमिलनाडु ने रुपये के प्रतीक को तमिल अक्षर श्घ्श्श् से बदल दियाए जिससे पता चलता है कि सरकार तमिल संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके विपरीतए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूरे भारत में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करने का समर्थन करती है। तमिलनाडु भाषाई विविधता को बढ़ावा देता है और अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीएमके पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को तब विरोध करना चाहिए था जब 2010 में यूपीए ने रुपये का प्रतीक अपनाया था। डीएमके केंद्र में सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन का हिस्सा थी।

तमिलनाडु 14 साल बाद पहली बार राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक को अस्वीकार करने वाला पहला राज्य है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति ;एनईपीद्ध के प्रति राज्य के चल रहे प्रतिरोध को दर्शाता है। रुपये का प्रतीक श्घ्श् उदय कुमार द्वारा बनाया गया थाए जो डीएमके के एक पूर्व विधायक के बेटे हैं और वर्तमान में आईआईटी में प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं।

2010 से पहलेए लोग अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपये के लिए रु या आईएनआर संक्षिप्त रूप का उपयोग करते थे। इसे कभी.कभी पाकिस्तानी और श्रीलंकाई रुपये के साथ भ्रमित किया जाता है। 2009 मेंए वित्त मंत्रालय ने रुपये के नये प्रतीक के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने डिजाइनरोंए कलाकारों और जनता को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया। लक्ष्य एक ऐसा प्रतीक बनाना था जो भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाता हो और इसकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता हो।यह प्रतीक दुनिया में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है। व्यापक शोध के बाद उदय कुमार धर्मलिंगम ने रुपया ;घ्द्ध प्रतीक बनाया। उन्होंने रुपये के लिए देवनागरी .रश् को रोमन श्आरश् के साथ जोड़ा। इससे प्रतीक को एक अनूठी भारतीय पहचान मिलती है और हर जगह के लोगों के लिए इसे पहचानना आसान हो जाता है। हालाँकिए तमिलनाडु सरकार इस प्रतीक का समर्थन नहीं करती है। वह अपनी भाषा को महत्व देती है और देवनागरी लिपि पर आधारित डिज़ाइन का उपयोग नहीं करना चाहती।

जब सरकार ने गुरुवार को विधेयक पेश कियाए तो तमिलनाडु राज्य विधानसभा के भाजपा सदस्यों और अन्नाद्रमुक ;एआईएडीएमकेद्ध सदस्यों ने स्टालिन के प्रतीक परिवर्तन का विरोध किया। यह भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और द्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को दर्शाता है। आर्य और द्रविड़ समुदायों के बीच संघर्ष एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मुद्दा है। तमिलनाडु तमिल भाषा का जोरदार बचाव करता है और रुपया प्रतीक को अस्वीकार करने वाला एकमात्र राज्य है। यह निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। मु यमंत्री स्टालिन का लक्ष्य भाषा के मुद्दे पर एक मजबूत छवि बनाये रखना है।

भारतीय रुपया वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ;आईएमएफद्ध इसे चीन के रेनमिनबी ;आरएमबीद्ध के साथ.साथ एक संभावित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में देखता है। कई देश अब भुगतान के लिए रुपया स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्तए भारत ने ऐसे व्यापार समझौते किये हैं जिनमें विनिमय के लिए रुपये का उपयोग किया जाता है।

समस्या का सार यह है कि क्या तमिलनाडु को दो या तीन भाषाओं के फॉर्मूले का उपयोग करना चाहिए। चिंता यह है कि तीसरी भाषा सीखना तमिलनाडु के छात्रों के लिए एक अतिरिक्त बोझ हो सकता है और इससे पूरे भारत में हिंदी का प्रभुत्व भी बढ़ सकता है। केंद्र और राज्य को एक साथ बैठकर एक उपयुक्त फॉर्मूला खोजना चाहिए।

विविध समाचार

बीआइटी मेसरा में अंतरराष्ट्रीय समेलन एफसीएमपीई वेल-एच 25 का होगा आयोजन

रांची २०/११ (संवाददाता): बीआइटी मेसरा के डिपार्टमेंट आफ फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड टेज़्नोलाजी, सेंटर फार फूड इंजीनियरिंग एंड टेज़्नोलाजी और डिपार्टमेंट आफ केमिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा युनिवर्सिटी आफ जार्जिया के सहयोग से इंटरनेशनल कांफ्रेंस आन फूड केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग फार वेलनेस एंड हेल्थ (एफसीएमपीई वेल-एच 25) की घोषणा की गई है।

एफसीएमपीई वेल-एच 25 एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सज़्मेलन है, जिसमें देश-विदेश से 400-500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 10 से 12 जुलाई तक आयोजित इस सज़्मेलन में शोधकर्ता, उद्योग जगत के लीडर्स, उद्यमी, नीति निर्माता और छात्र शामिल होंगे। सज़्मेलन का विषय सस्टेनेबल प्रोसेसिंग टेज़्नोलाजीज फार फूड सिज़्योरिटी, पज़्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन थ्रू एकेडमिया-इंडस्ट्री कोलाबोरेशन होगा, जो अकादमिक-उद्योग जगत के बीच साझेदारियों को बढ़ावा देगा। विश्वस्तरीय विशेषज्ञों की ओर से व्याज़्यान, टेज़्निकल पेपर प्रजेंटेशन, पैनल चर्चा, पोस्टर सत्र, ज़्लैश चर्चा, क्विज और औद्योगिक प्रदर्शनी कार्यक्रम होगा, जहां फूड बायोटेज़्नोलाजी एवं सस्टेनेबल फूड प्रोसेसिंग में आधुनिक इनोवेशन और समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। बीआइटी लालपुर में आयोजित प्रेसवार्ता

के दौरान डा. अनुपम राय ने बताया कि सज़्मेलन का उद्देश्य ऐसी सस्टेनेबल फूड प्रोसेसिंग तकनीकों को बढ़ावा देना है जो खाद्य सुरक्षा, पोषण और गुणवज़ा को सुनिश्चित करती हैं। विशेषकर देश की विकसित होती बायोइकोनोमी में अकादमिक इनोवेशन और औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच के अंतर को दूर करना शामिल है। ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोगपूर्ण उद्यमों के माध्यम से राष्ट्रीय मिशन जैसे नेशनल बायोटेज़्नोलाजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी और आत्मनिर्भर भारत को समर्थन प्रदान करना युवा शोधकर्ताओं, नए विज्ञानियों एवं स्टार्ट-अप्स को ऐसा मंच प्रदान करना जहां उन्हें अपने इनोवेशन को दर्शाने तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और उद्योगों के साथ साझेदारियों का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा, यह सज़्मेलन सिर्फ एक अकादमिक मंच नहीं बल्कि राष्ट्रीय निर्माण का प्लेटफार्म है जो देश को सस्टेनेबल फूड बायोटेज़्नोलाजी में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करेगा।झारखंड के जैविक संसाधनों, वन उत्पादों एवं कृषि आधारित उद्यमों की क्षमता पर विशेष फोकस जो क्षेत्र के समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगा।

सज़्मेलन का उद्देश्य कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, फंज़्शनल एवं फोर्टिफाइड फूड को बढ़ावा देना तथा व्यक्तिगत पोषण एवं खाद्य प्रत्यास्थता के लिए एआइ, आइओटी एवं 3डी फूड प्रिंटिंग एवं माइक्रो-बायोम आधारित इनोवेशन को प्रोत्साहित करना है।

यह सज़्मेलन विभिन्न सेज़्टरों के बीच बातचीत के लिए हब की भूमिका निभाएगा। यह बीआइटी मेसरा तथा उद्योग जगत के दिग्गजों, बायोटेक स्टार्टअप्स, फूड टेज़्नोलाजी फर्म, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करेगा। टेज़्नोलाजी के आदान-प्रदान, उद्यमों के विकास तथा खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़े पैमाने के इनोवेशन को बढ़ावा देगा।

सज़्मेलन के दौरान प्रस्तुत किए गए चुनिंदा उच्च गुणवज़ा के पेपर्स को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा स्कोप्स इंडेज़्स्ड इंटरनेशनल जर्नल के विशेष अंक की योजना भी बनाई गई है। प्रेसवार्ता के दौरान आयोजन के सह संयोजक डा. अमित तिवारी, डा. मृणाल पाठक समेत अन्य उपस्थित रहे। डा. बापी गोरेन (कन्वेनर 2) फार्मास्युटिक बायोटेज़्नोलाजी एवं सीएनएस ड्रग डिलीवरी में विशेषज्ञ हैं, जो बहु-आयामी इनोवेशन एवं विश्वस्तरीय विज्ञानी नेटवर्क के लिए जाने जाते हैं।

रेलवे ट्रैक पर गूंजी गजराज के बच्चे की किलकारी, घंटों थमा रहा ट्रैफिक

रांची २०/११ (संवाददाता): हजारीबाग-बरकाकाना रेलवे लाइन पर एक भावुक कर देने वाली और हृदयस्पर्शी घटना सामने आई है। जहां गढ़वा गांव के पास एक गर्भवती हथिनी ने सीधे रेलवे ट्रैक पर एक बच्चे को जन्म दिया। इस असाधारण घटना के कारण ट्रेन संचालन को दो घंटे के लिए रोकना पड़ा, ज़्योंकि रेलवे अधिकारियों ने हाथी के बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी को प्राथमिकता दी। यह घटना तब हुई जब हाथियों का एक झुंड, जो लगभग 15 दिन पहले सरवाहा वन क्षेत्र में दाखिल हुआ था। इस झुंड से एक गर्भवती हथिनी भटक कर हज़ारीबाग-बरकाकाना रेलवे लाइन के पास आ गई। जिन ग्रामीणों ने हथिनी को परेशानी में देखा, उन्होंने तुरंत वन विभाग और रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर रामगढ़ के मंडल वन अधिकारी नीतीश कुमार ने तत्काल रेलवे प्रशासन को सूचित किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए, रेलवे ने हज़ारीबाग से बरकाकाना जा रही एक मालगाड़ी को रोक दिया, जिससे प्रसव के दौरान हथिनी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सफल प्रसव एवं बच्चे को हटाने के बाद ट्रेनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया। यह घटना मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व की चुनौतियों पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां वन गलियारे मानव बुनियादी ढांचे से मिलते हैं। यह स्थानीय ग्रामीणों, वन विभाग के अधिकारियों और रेलवे अधिकारियों के सराहनीय प्रयासों को भी दर्शाता है, जिन्होंने वन्यजीवों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम किया। ट्रैक पर नवजात बछड़े का अपनी मां के साथ सुरक्षित खड़ा होना कई लोगों के दिलों को छू गया और वन्यजीव आवासों का सज़्मान और संरक्षण करने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है।

आज का राशिफल

मेष - आज के दिन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृज़ियाँ विशेष रहेंगी। मन में द्विधा रहने से ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। पैसे की लेन-देन या आर्थिक व्यवहार न करने की गणेशजी की सलाह है।

वृषभ - गणेशजी कहते हैं कि व्यापार में वृद्धि होने के साथ व्यापार के सज़्बंध में सौदे लाभदायक साबित होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। बुजुर्गों तथा मित्र मंडल से लाभ और सुखद क्षणों का अनुभव मिलेगा।

मिथुन - शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। नौकरी - व्यवसाय में आपके परिश्रम का मुआवजा मिलता हुआ प्रतीत होगा। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कर्क - गणेशजी कहते हैं कि आज आपकी भाग्य वृद्धि के साथ आकस्मिक धन लाभ होगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के प्रयास सफल होंगे। तथा विदेश से अच्छे समाचार आएँगे।

सिंह - आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। निषेधात्मक विचार आपको गलत मार्ग पर न ले जाए, उसका ध्यान रखने के लिए गणेशजी कहते हैं।

कन्या - गणेशजी की कृपा से दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ज़्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। मनोरंजन की प्रवृज़ियों में भाग लेंगे। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी।

तुला - गणेशजी कहते हैं कि सामान्ज रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति के भी तबीयत में सुधार होगा। घर में सुख- शांति के वातावरण में आप समय व्यतीत करेंगे। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा।

वृश्चिक - आज यात्रा प्रवास का आयोजन न करने की सलाह गणेशजी देते हैं। स्वास्थ्य के सज़्बंध में चिंतित रहेंगे। संतानों के सज़्बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें।

धनु - गणेशजी कहते हैं कि आज आपको अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव खड़े होने की संभावना है। मन में उठनेवाली द्विधाओं से आप मानसिक उचाट अनुभव करेंगे।

मकर - आज आप रणनीति में शत्रुओं को परास्त करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। सफलता मिलेगी। आप हरेक कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। व्यापार-धंधे में लाभ होगा।

कुंभ - गणेशजी बताते हैं कि मन में द्विधाएँ खड़ी होने से आप कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुँच सकेंगे। महज़्वपूर्ण निर्णय न लें। वाणी पर संयम नहीं रहनेसे पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की संभावना है।

मीन - आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। नए कार्य हाथ में लेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। धार्मिक मांगलिक प्रसंगों में जाएँगे।

खुशखबरी! कोडरमा-तिलैया के बीच दिसंबर से दौड़ेंगी ट्रेनें, 4 सुरंग और 7 पुल करेंगी पार

कोडरम २०/११ (संवाददाता): झारखंड व बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाला कोडरमा-तिलैया रेलखंड आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। इस रूट पर चार सुरंग व सात पुल से होकर गुजरने वाली ट्रेनें यात्रियों को सुखद अहसास कराएगी। ज़्पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर कोडरमा-तिलैया राजगीर रेल लाइन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने समयसीमा में काम पूरा करने को लेकर मानिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में मुज़्य प्रशासनिक पदाधिकारी निर्माण उज़ार रामजनम, मुज़्य प्रशासनिक पदाधिकारी दक्षिण रामाश्रय पांडेय एवं निर्माण कंपनी राइटस के अधिकारीगण

शामिल थे। करीब 1625 करोड़ की लागत से बन रहा 65 किलोमीटर लंबा कोडरमा-तिलैया रेलखंड दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इसमें सुरंग, पुल और स्टेशनों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

रेलवे अधिकारी ने बताया कि अब तक 50 किलोमीटर रेल लाइन का काम पूर्ण हो चुका है। इसमें 350 मीटर, 305 मीटर, 255 मीटर व 250 मीटर की चार सुरंगें बन रही है। दिसंबर तक रेलमार्ग चालू होता है तो पर्यटकों के लिए बेहतर होगा।

इस रेलखंड से राजगीर, नालंदा, पावापुरी व ककोलत जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सीधे जुड जाएंगे। इस रेलखंड के शुरू होने से राजगीर, तिलैया, नवादा, बरही, कोडरमा जैसे क्षेत्रों के लोगों को रेलवे की बेहतर सुविधा मिलेगी। आम जनों के लिए इलाज, शिक्षा, रोजगार और व्यापार के रास्ते खुलेंगे। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, निर्माण पूरा होते ही इस रेलखंड पर यात्री व मालगाड़ियां दोनों चलेंगी। यह रेलखंड बन जाने से राजगीर से रांची का सफर तीन से चार घंटे कम हो जाएगा। रेलवे ने इस रेलखंड में वाइल्डलाइफ कारिडोर बनाने की योजना बनाई है, ताकि हाथी व अन्य वन्यजीवों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। रेलखंड के स्टेशन परिसर में नवादा व कोडरमा की लोक कलाओं व काष्ठ शिल्प की झलक दिखेगी। बजट में इस रेल लाइन के निर्माण के लिए 446.74 करोड़ का आवंटन किया गया है। वर्ष 2004 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार के समय इस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी।

राहगीरों को रौंदते हुए आगे बढ़ी एसयूवी, बिजली के खंभे से जा टकराई

रांची २०/११ (संवाददाता):राजधानी रांची के मोरहाबादी क्षेत्र स्थित आज़्सीजन पार्क के निकट सोमवार की रात एक अनियंत्रित एसयूवी कार ने पांच लोगों को रौंद डाला। इस घटना में रांची के डोरंडा स्थित नेपाल हाउस में जल संसाधन विभाग में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह की मौत हो गई ।वहीं प्रशाखा पदाधिकारी की पत्नी मधु रानी के अलावा मोरहाबादी की सरिता देवीए संतोष कुमार एवं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। रिज़्स और राम प्यारी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। इधरए घटना को अंजाम देने के बाद चालक कार छोड़कर फ़रार हो गयाए जबकि पुलिस ने कार जज़्त करने के साथ ही उसके एक दोस्त को हिरासत में ले लिया है। प्रशाखा पदाधिकारी मोरहाबादी स्थित एक अपार्टमेंट में रहते थे। कार के आगे व पीछे सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया लिखा है। साथ ही उसपर एडवोकेट का लोगो भी लगा हुआ है।जानकारी के अनुसार एसयूवी चालक मोरहाबादी स्थित रूईन हाउस से शराब पीने के अपनी कार ;संज़्या डज़्ल्यूबी 06 जेड.1160द्ध लेकर निकला। चालक के साथ उसके दो दोस्त भी कार में सवार थे। नशे में धुत चालक कार इतनी तेज गति से चला रहा था कि उसने मान्या पैलेस के पास सबसे पहले एक कार को टक्कर मारी। भागने के क्रम में आज़्सीजन पार्क के निकट पैदल जा रहे प्रशाखा पदाधिकारी और उनकी पत्नी को धक्का मार दिया। दोनों सड़क के दूसरी ओर गिर पड़े। एसयूवी ने कुछ ही दूरी पर पैदल व स्कूटी से जा रहे तीन अन्य लोगों को भी ठोकर मारी। इससे वे तीनों भी सड़क पर गिर गए।

कांग्रेस कमेटी के गठन में देरी की वजह आई सामने, अब इस आधार पर जारी होगी नई लिस्ट

रांची २०/११ (संवाददाता): झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। कमेटी में कुछ और नए चेहरे जुड़ेंगेए जिनमें अनुसूचित जाति और ओबीसी समुदाय के लोगों के जुड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। नई कमेटी अपेक्षाकृत छोटी हो सकती है। इसको लेकर गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अपने दौरे के क्रम में सभी जिलों में और प्रदेश स्तर पर सक्रिय चेहरों की पहचान कर रहे हैंए ताकि कमेटी के विस्तारीकरण पर कहीं से कोई सवाल न उठे। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर काम लगभग पूर्ण हो चुका थाए लेकिन इसी बीच तत्कालीन प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर को झारखंड से हटाकर अन्य राज्य की जिज़्मेदारी दे दी गई।गुलाम अहमद मीर को झारखंड से हटाए जाने की वजह से पूरा समीकरण गड़बड़ हो गया और कमेटी का गठन टल गया। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने अपने.अपने स्तर से लोगों की पहचान कर ली है और माना जा रहा है कि शीघ्र ही कमेटी का अंतिम स्वरूप सभी के सामने होगा। कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्षए सचिवए संयुक्त सचिव आदि तमाम पदों पर नेताओं.कार्यकर्ताओं का चयन होगा और इस प्रकार लगभग सौ लोगों की कमेटी बनकर तैयार होगी। अभी तक जो भी कमेटी बनी हैए उसमें सदस्यों की संज़्या सवा सौ के आसपास रही है।

इस बार अपेक्षाकृत छोटी कमेटी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सचिव स्तर के पदों में कुछ कमी की जा सकती है। उपाध्यक्षों की संज़्या भी पहले से कम हो सकती है। सरायकेला.खरसांवा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रविवार को कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार की अध्यक्षता में रेलवे मैदान स्थित सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आसन्न निकाय व पंचायत चुनाव को देखते हुए जिले के पदाधिकारी एवं प्रमुख कांग्रेसियों के साथ रणनीतियों पर चर्चा की गई। सर्वसज़्मति से आदित्यपुर सरायकेला व कपाली नगर निकाय चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने पर सहमति जताई गई। संबंधित निकायों के सभी वार्डों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी उतारने पर विचार किया गया।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

क़लिंग समाचार | राउरकेला, शुक्रवार 21 नवंबर 2025 | पृष्ठ-6

वन परिवर्तन प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने पर जोर

भुवनेश्वर २०/११ (संवाददाता): महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने हाल ही में वन परिवर्तन प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही हेतु अपनी तीसरी मासिक समन्वय बैठक आयोजित की।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुज्य सचिव सत्यब्रत साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वन मंजूरी की आवश्यकता वाली प्रमुख परियोजनाओं, जैसे सड़क मार्ग, रेलवे, दूरसंचार अवसंरचना और इस्पात संयंत्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), भारतीय रेलवे, ओपीटीसीएल, जीएसआई और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआईएल), बीएसएनएल और सेल जैसी कंपनियों के अंतर्गत आने वाली प्रमुख परियोजनाओं के लिए वन परिवर्तन प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान, साहू ने कई प्रमुख परियोजनाओं, जिनमें कैपिटल रीजन रिंग रोड परियोजना, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा गोरुमहिसानी नई रेलवे लाइन और रिलायंस जियो की 4जी-आधारित मोबाइल सेवा परियोजना शामिल हैं, के अद्यतनों की समीक्षा की। एसीएस के अनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और आरजेआईएल द्वारा विशेष रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने और मोबाइल टावर लगाने के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त, ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अन्वेषण प्रस्तावों में भी सकारात्मक प्रगति देखी गई है। एसीएस ने राजधानी क्षेत्र रिंग रोड (सीआरआरआर-ढ्ढ और सीआरआरआर-ढ्ढढ्ढ) परियोजनाओं में हुई प्रगति की भी प्रशंसा की, जो समीक्षा के मुज्य बिंदुओं में से एक थीं। हालाँकि, एसीएस ने प्रधान मुज्य वन संरक्षक (वन्यजीव) को वन्यजीव संबंधी मुद्दों का अविलंब समाधान करने का निर्देश दिया ताकि आगे कोई बाधा न आए। बैठक का प्राथमिक उद्देश्य वन डायवर्जन प्रस्तावों की अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाना था, जो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

एसीएस ने सभी क्षेत्रीय मुज्य वन संरक्षकों (आरसीसीएफ) और प्रभागीय वन अधिकारियों (डीएफओ) को इन प्रस्तावों के प्रसंस्करण को प्राथमिकता देने और स्थानीय स्तर पर किसी भी लंबित मुद्दे को निपटाने का निर्देश दिया। बैठक में उपयोगकर्ता एजेंसियों को एक सज्त चेतावनी भी दी गई, जिसमें उनसे बिना किसी देरी के सभी आवश्यक दस्तावेज़—जैसे नज़्शे, सर्वेक्षण रिपोर्ट और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन—जमा करने का आग्रह किया गया। अतिरिक्त मुज्य सचिव ने वन विभाग से उन उद्योगों के साथ और अधिक घनिष्ठ सहयोग करने का आग्रह किया जिन्होंने सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। विभाग को कल्याणी स्टील्स लिमिटेड जैसे उद्योगों के वन परिवर्तन प्रस्तावों को सुगम बनाने के लिए कहा गया।

आरएसपी की नए प्लेट मिल महामरामज़ी-2025 कार्य के दौरान नए सुरज़्श कोण के साथ सुरक्षा ढांचे में आई मजबूती

राउरकेला २०/११ (संवाददाता): नए प्लेट मिल (एनपीएम) में चल रहे कैपिटल रिपेयर-2025 के दौरान सुरक्षा प्रथाओं को और मजबूत करने और कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित सुरक्षा कोण (सेज़्टी कॉर्नर) स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि, मिल का 10 दिवसीय महामरामजी अभियान शुरू हुआ था। विशेषत: सुरक्षा सुविधा व्यापक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्थाओं से लैस है, जिसमें तीनों शिज़्टों में तैनात प्रशिक्षित प्राथमिक उपचारकर्ता, अग्निशामक यंत्र, ओआरएस युक्त पेयजल, एक विश्राम क्षेत्र और प्रमुखता से प्रदर्शित आपातकालीन संपर्क विवरण शामिल हैं। इसके अलावा, सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य-विशिष्ट ज़्या करें और ज़्या न करें और जीवन रक्षक तकनीकों पर सूचनात्मक पोस्टर प्रदर्शित किए गए हैं। सुरक्षित कार्य प्रथाओं को सुदृढ़ करने और मरज़्मती गतिविधियों में लगे कर्मियों के बीच उच्च स्तर की सुरक्षा जागरूकता बनाए रखने के लिए सभी शिज़्टों में नियमित टूल बॉज़्स वार्ता (टीबीटी) आयोजित की जा रही है। यह पहल मुज़्य महाप्रबंधक (एनपीएम एवं एसपीपी), श्री आर के मुदुली द्वारा किया गया, जिसमें महाप्रबंधक (प्रचालन) एवं अनुभाग प्रमुख, श्री एन महापात्र, महाप्रबंधक (यांत्रिक) एवं अनुभाग प्रमुख, श्री सुधाकर सुब्रमण्यम और उप महाप्रबंधक (विद्युत), श्री अमित रावत का सक्रिय सहयोग एवं समन्वय शामिल था। सेज़्टी कॉर्नर स्थापना गतिविधि का समग्र समन्वय विभागीय सुरक्षा अधिकारी (एनपीएम), श्री सुमन कुमार द्वारा किया गया।

गांव में संदिग्ध खाद्य विषाक्तता से 11 लोग बीमार

गंजम २०/११ (संवाददाता): गंजम ज़िले के पात्रापुर प्रखंड के सामंतियापल्ली गाँव में कथित तौर पर दूषित भोजन खाने से कम से कम 11 लोग बीमार पड़ गए। यह घटना गुरुवार रात को सामने आई, जिससे स्थानीय निवासियों में तनाव और चिंता फैल गई। सूत्रों के अनुसार, कई ग्रामीण सामंतियापल्ली में एक निवासी के घर भोजन के लिए इकट्ठा हुए थे। खाना खाने के कुछ ही देर बाद, उनमें से कई लोगों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। हालत बिगड़ने पर, प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा के लिए पात्रापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अस्पताल के चिकित्सा कर्मचारियों ने पुष्टि की कि ये लक्षण संभवत: भोजन विषाक्तता के संकेत हैं। प्रभावित 11 लोगों में से एक की हालत गंभीर बताई गई है।

उसे उन्नत उपचार के लिए बरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बीच, पात्रापुर अस्पताल में इलाज करा रहे कई अन्य लोगों को उनकी हालत में सुधार होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। हालाँकि, संदूषण के सही कारण की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों को संदेह है कि भोजन अनुचित तैयारी या कुछ सामग्रियों के संदूषित होने के कारण विषाक्त हो गया होगा। अधिकारी सटीक कारण जानने के लिए जाँच कर सकते हैं। अभी तक, चिकित्सा अधिकारियों ने इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जाँच जारी रहने तक आगे की जानकारी का इंतज़ार है।

बणई अनुमंडल में पर्यटन स्थलों की उपेक्षा

राउरकेला २०/११ (संवाददाता): प्राकृतिक मनोरम स्थलों से परिपूर्ण बणई अनुमंडल में पर्यटन की उपेक्षा की जा रही है। पर्यटन विभाग व वन विभाग की ओर से खंडाधार जलप्रपातए देवधरए तथा कोइड़ा में प्राकृतिक पर्यटन स्थल के विकास के लिए काम हुआ है पर अब भी गुरुंडिया के बादल गिरि जलप्रपातए ब्राह्मणी नदी में सिचाई परियोजनाए सरसरा में सिचाई परियोजनाए कोइड़ा में कुराड़ी नाले में सिचाई परियोजना का काम कर आसपास के क्षेत्र में पर्यटन स्थल बनाए जा सकते हैं। गुरुंडियाए लहुणीपाड़ाए कोइड़ व बणई ज़्लाक के जल प्रपात हैं जिनका विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जा सकता है। सुंदरगढ़ जिले में बणई अनुमंडल में ही ओडिशा का सबसे ऊंचा जलप्रपात खंडाधार स्थित है। राज्य सरकार की ओर से यहां पर्यटको को आकृष्ट करने के लिए इको टूरिज्म में शामिल किया गया है तथा इस क्षेत्र में वन विभाग की ओर से विकास का काम किया जा रहा है।

टेनसा में पहाड़ी की ऊंचाई पर गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं एक महीने के अंदर आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जायेगा। ब्राह्मणी नदी पर दार्जिंग घाटए वीरतोला घाट के साथ रुकड़ा सिचाई परियोजनाए सरसरा में बड़जोर सिचाई परियोजनाए कोइड़ा ज़्लाक में कुराली सिचाई परियोजना के आसपास पर्यटन विकास के लिए पर्याप्त संभावना है।

इसके अलावा बणइ, गुरुंडिया, लहुणीपाड़ा व कोइड़ा ज़्लॉक क्षत्र में घाग, मिरिग लेउटुणी, बादलगिरि, घोराघर, खंभेश्वरी, सूखानाला, मानसमुंडी आदि जल प्रपात लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं।

इस महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा लिए तैयार

भुवनेश्वर २०/११ (संवाददाता): राज्य के अधिकारियों के अनुसार, ओडिशा सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की27 नवंबर को राज्य की दो निर्धारित यात्राओं की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को राष्ट्रपति छज़ीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जाते समय झारसुगुड़ा के वीर सुरेंद्र साईं (वीएसएस) हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए रुकेंगी। एक हज़्ते बाद, वह ओडिशा की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएँगी, जिसके दौरान वह राजभवन परिसर में एक नए अतिथि गृह का उद्घाटन करेंगी और ओडिशा विधानसभा को संबोधित करेंगी। वह 28 नवंबर को राज्य से प्रस्थान करेंगी. मुज़्य सचिव मनोज आहूजा ने आगामी यात्राओं पर एक उच्च-स्तरीय तैयारी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विकास आयुक्त अनु गर्ग, अतिरिक्त मुज़्य सचिव एस साहू, पुलिस महानिदेशक वाईबी खुरानिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आहूजा ने कहा, हालाँकि राष्ट्रपति 20 नवंबर को झारसुगुड़ा में केवल एक संक्षिप्त ठहराव करेंगी, फिर भी सुरक्षा, स्वास्थ्य और रसद सहित सभी व्यवस्थाएँ पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए।

27 नवंबर के दौरे के लिए, मुज़्य सचिव ने गृह, स्वास्थ्य और अन्य विभागों को निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए। विधानसभा परिसर में अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी की अध्यक्षता में एक अलग समीक्षा बैठक भी हुई।

राउरकेला इस्पात सयंत्र में सुरक्षा पुरस्कार समारोह आयोजित

राउरकेला २०/११ (संवाददाता): ओडिशा आपदा तैयारी दिवस के मौके पर आयोजित सुरक्षा प्रश्नोज़री के विजेताओं को सज़्मानित करने के लिए 10 नवंबर, 2025 को नया सीसीडी सज़्मेलन कक्ष में एक सुरक्षा पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुज़्य महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएँ), श्री हीरालाल महापात्र, मुज़्य महाप्रबंधक (सीओ एवं सीसीडी), श्री राकेश जोशी, महाप्रबंधक प्रभारी (सीसीडी), श्री बी. के. तिवारी भी मौजूद थे। गणमान्यों ने पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

प्रश्नोज़री में कुल 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया। छह क्विज़ विजेताओं में शामिल ठेका श्रमिक, साइट पर्यवेक्षक और सुरक्षा पर्यवेक्षक के साथ ही छह सुरक्षा के प्रति जागरूक कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य प्रथाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सज़्मानित किया गया।

अपने संबोधन में, श्री हीरालाल महापात्र ने जहरीली गैस सुरक्षा पर बात की, जिसमें खतरे की पहचान, रोकथाम, अलगाव (आइसोलेशन), पर्जिंग, वेंटिंग और परमिट टू वर्क प्रणाली शामिल थे।

श्री राकेश जोशी ने भोपाल और चेरनोबिल जैसी पिछली औद्योगिक आपदाओं से सीखने पर जोर दिया, और दोहराया कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है।

श्री बी. के. तिवारी ने मौजूदा सुरक्षा प्रणालियाँ को मजबूत करने के तरीकों पर प्रकाश डाला।

शुरुआत में, महाप्रबंधक (सुरक्षा), श्री अबकाश बेहरा ने सभा को आपातकालीन तैयारी और ज़्लास्ट फर्नेस गैस, एलडी गैस और कोक ओवन गैसों को सुरक्षित रूप से संभालने के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोयला रसायन विभाग के कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के बीच आपदा तैयारी और गैस और रसायन सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।

सहायक महाप्रबंधक (सीसीडी), श्री एम. के. पाणिग्रही ने कार्यक्रम का संचालन किया जबकि उप महाप्रबंधक और विभागीय सुरक्षा अधिकारी (सीसीडी), श्री सुवेंदु पटनायक और उप प्रबंधक (सुरक्षा), श्री आर एन पाणिग्रही ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का समन्वय किया।

पर्यटन स्थल की सूची में जिले के 14 स्थान शामिल

राउरकेला २०/११ (संवाददाता): पिकनिक का समय आते ही पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। इसे आकर्षक बनाने के लिए जिला पर्यटन विभाग की ओर से हर साल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी विभाग की ओर से इको रिट्रिट की व्यवस्था की गई है। विभाग की ओर से करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं पर स्थिति में आशानुरूप बदलाव नहीं देखा जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सुंदरगढ़ जिले के 14 स्थानों को राज्य पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया गया है पर इसके विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य नहीं हो रहे हैं। पर्यटन स्थल का विकास कर पर्यटकों को आकृष्ट करने एवं इससे अधिक राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर काम नहीं हो पाया है।पर्यटन स्थलों के विकास से पर्यटकों की संज़्या बढ़ेगी जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। पर्यटन विभाग की ओर से इसे लेकर पर्यटन स्थलों का नज़्शा तैयार किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सुंदरगढ़ जिले के 14 स्थान इस सूची में शामिल हैं। इसमें वेदव्यास शैव पीठ व संगमए हेमगिर जूना गढ़ए लेफ्रीपाड़ा ज़्लॉक का उषाकोठीए देवदरहए राजगांगपुर में घोघड़धामए मंदिरा डैमए लहुणीपाड़ा में दर्जिंगए मिरिग खोजए टेनसाए लाठीकटा ज़्लॉक में पीतामहल डैमए बड़गांव में छतरी हिलए कुआरमुंडा ज़्लॉक में आमको सिमको शामिल हैं। इस क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार का ध्यान नहीं है। आमको सिमको शहीद स्थल में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 2017 में दो करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। विभिन्न कारणों से पानपोष आइटीडीए में राशि पड़ी रही। राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद जनवरी 2021 में काम शुरू हुआ। बणई ज़्लॉक के खंडाधार जलप्रपात के लिए भी चार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। ओडिशा पर्यटन विभाग की ओर से काम शुरू नहीं किया गया है। जिला पर्यटन अधिकारी निरंजन महापात्र के अनुसार जिले में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं आया है। खंडाधार जलप्रपात के लिए चार करोड़ रुपये मिले हैं जिससे विकास का काम होगा। इसमें शौचालयए पार्क स्थलए पशु पक्षी के लिए प्राकृतिक परिवेश बनाया जाएगा जिससे पर्यटक यहां आएंगे। रोप.वे का प्रस्ताव फ्लिहाल रद किया गया है। पीतामहाल डैम में भी नौका विहार की योजना थी पर यह प्रस्ताव तक ही सीमित है। वेदव्यास के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से 1ण्28 करोड़ रुपये खर्च किए गए.